भारत-अमरीका नागरिक परमाणु सहयोग समझौता-2008 Indo-US Civil Nuclear Cooperation Agreement 2008) अक्तूबर 2008 में भारत तथा अमरीका ने नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके अधीन भारत को परमाणु आपूर्ति समूह के सभी 45 देशों के साथ परमाणु व्यापार करने और अपनी परमाणु ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिल गया। इसके साथ ही भारत ने भी अपने 14 परमाणु संयों को अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के निरीक्षण के लिए खोल दिया परन्तु भारत ने NPT पर हस्ताक्षर न करने की नीति अपनाए रखी और स्वेच्छा और परमाणु परीक्षण न करने का निर्माय बनाए रखा। पाकिस्तान के साथ किसी ने परमाणु सहयोग समझौठा तो नहीं किया लेकिन इसके द्वारा परमाणु शस्त्रों को बनाए रखने की स्थिति को विश्व ने अप्रत्यक्ष रूप में सहन किए रखा। लेकिन उत्तरी कोरिया तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के कारण एक बार फिर परमाणु अप्रसार बनाम प्रसार का मुद्दा विश्व राजनीति में अधिक सक्रिय रूप में उभर कर सामने आया। आज भी स्थिति ऐसी ही है।

सितम्बर 2009 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) के पक्ष में प्रस्ताव पास करके सभी देशों.. जिन्होंने अभी इस सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, को इसे स्वीकार करने की सिफारिश की लेकिन भारत जैसे देशों ने अभी भी परमाणु अप्रसार सन्धि (NPT) का विरोध करना जारी रखा क्योंकि ये देश इस सन्धि को अधूरी और पक्षपातपूर्ण सन्धि मानते हैं।

37 उत्तरी कोरिया एवं ईरान की परमाणु नीतियाँ और परमाणु अप्रसार का मुद्दा (Nuclear Policies of North Korea and Iran a.id the Issue of Nuclear Non-Proliferation) सन 2006 में उत्तरी कोरिया ने परमाणु परीक्षण करके अपने आपको परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश घोषित कर दिया था लेकिन फिर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव, विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, दक्षिणी कोरिया एवं जापान के दबाव अधीन उत्तरी कोरिया ने वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपनी इस परमाणु नीति को समाप्त कर दिया था लेकिन 2009 में उत्तरी कोरिया ने फिर परमाणु परीक्षण और मिळाईल परीक्षण करके अपने आपको परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश घोषित कर दिया। इसके बाद उत्तरी कोरिया ने अपना परमाणु शस्त्र विकास प्रोग्राम तथा मिसाइल विकास कार्यक्रम चालू रखा। जनवरी 2016 में उत्तरी कोरिया ने एक परमाणु परीक्षण करके यह घोषित कर दिया कि उसने हाईड्रोजन चम्म को बना लिया है। उसके इस कार्य की सभी प्रमुख देशों विशेषकर संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत, यूरोपीय संघ के देशों तथा यहां तक कि धीन ने भी आलोचना की अन्तेराष्ट्रीय स्तर पर यह सोच बनी कि उत्तरी कोरिया को

अपनी परमाणु विस्तार नीति को त्याग देने के लिए विवश करना बहुत आवश्यक हो गया, परन्तु सच्चाई यह है कि आज तक

ऐसी सोच के अनुसार कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया गया है।

इसी तरह 2013 तक ईरान ने भी अपनी परमाणु तकनीक को विकसित करने की नीति जारी रखी और उसने यूरेनियम गुणवत्ता वृद्धि (Uranium Enrichment) तकनीक विकसित करने की नीति को जारी रखा। सितम्बर 2009 में यह तथ्य सामने आया कि ईरान के पास ऐसे दो संयंत्र थे, यहा कि पहले यह सूचना थी कि उसके पास केवल ही ऐसा संयंत्र था। संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बहुत-से देशों ने ऐसी स्थिति को परमाणु प्रसार करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया क्योंकि उच्च क्षमता वाले परमाणु ईंधन का प्रयोग तो परमाणु शस्त्र निर्माण के लिए ही किया जाता है। इस स्थिति में विश्व के बहुत से देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग (International Atomic Energy Commission) ने ईरान के साथ वार्तालाप द्वारा ईरान को अपना परमाणु शस्त्र प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को आरम्भ किया। लगभग दो वर्ष के वार्तालाप के बाद 2014 में ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया। अमरीका के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग तथा कुछ अन्य देशों के साथ ईरान के साथ एक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। इसके अन्तर्गत ईरान ने अपना युरेनियम संर्वधन प्रोग्राम को त्याग दिया तथा जितना भी यूरेनियम संर्वधन किया । उसमें से 98 प्रतिशित सर्वधित यूरेनियम को अपने क्षेत्र से बाहर भेज दिया। इसके बदले में ईरान के ऊपर लगे आर्थिक तथा अन्य प्रतिबंध (Economic and Other Sanctions) समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जनवरी 2016 में यह समझौता लागू हो गया और 17 जनवरी के दिन अमरीका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध समाप्त कर दिए और यह घोषणा भी कर दी कि ईरान का जो भी पैसा विदेशों में रूका पड़ा था वह ईरान को वापिस मिलना शुरू हो जायेगा। लेकिन क्योकि इस समझौते के बाद ईरान द्वारा एक मिसाइल परीक्षण किया गयाथा इसलिए अमरीका ने ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों की एक नई व्यवस्था को भी लागू कर दिया। इसके विरूद्ध ईरान क्या प्रतिक्रिया

करता है यह तो समय ही बताएगा, परन्तु, एक तथ्य निश्चित है कि ईरान अब एक अपने परमाणु ऊर्जा शान्तिपूर्ण विकास

प्रोग्राम के रूप में ही संचालित के लिए विवश रहेगा। आज विश्व में इस बात का डर बना हुआ है कि परमाणु शस्त्र अथवा परमाणु तकनीक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादियों के हाथ में पहुंच सकती है जो कि विश्व के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए आज यह आवश्यक है कि परमाणु अप्रसार के पक्ष में कार्य किया जाए। इसके उद्देश्य के सम्बन्ध में सभी देशों को परमाणु निशस्त्रीकरण को अपनाकर एक अन्तर्राष्ट्रीय

सन्धि के अधीन अपने सभी परमाणु शस्त्र नष्ट कर देने चाहिए।

समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में परमाणु अप्रसार बनाम परमाणु प्रसार का मुद्दा एक महत्वपूर्ण एवं उलझावपूर्ण मुद्दा

बना हुआ है। परमाणु निःशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियन्त्रण की ओर प्रगति काफी धीमी और दिशाहीन ही प्रतीत होती है।